The Research Dialogue
International Open Access, Peer Reviewed & Refereed Journal
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 5 | Issue 3 | October 2026
ISSN: 2583-438X (Online)
Impact Factor: SJIF: 5.087, RPRI 4.79/6.69
Website: https://theresearchdialogue.com/

भारत–अमेरिका संबंधों के आर्थिक और सामरिक आयाम: व्यापार, निवेश, सेवा-क्षेत्र तथा रक्षा सहयोग में अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन

अरुण कुमार[1], डॉ. सुमन[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, राजस्थान।
[2]शोध निदेशक, राजनीति विज्ञान विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, राजस्थान।

DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i3.27

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 10-09-2026

Accepted: 25-10-2026

Published: 31-10-2026

Corresponding Author:
अरुण कुमार

प्रमुख शब्द: भारत–अमेरिका संबंध; द्विपक्षीय व्यापार; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; सेवा-क्षेत्र; रक्षा सहयोग; आर्थिक सुरक्षा; रणनीतिक स्वायत्तता; हिंद-प्रशांत।

OPEN ACCESS

सारांश

भारत–अमेरिका संबंध आर्थिक सहभागिता, तकनीकी सहयोग और सामरिक हितों के अंतर्संबंध का महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, सेवा-क्षेत्र और रक्षा सहयोग के प्रमुख आयामों का अध्ययन करते हुए उनके विस्तार की संभावनाओं तथा संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-अभिकल्प पर आधारित है और इसमें द्वितीयक आँकड़ा-संग्रह पद्धति अपनाई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय तथा आधिकारिक संयुक्त वक्तव्यों से प्राप्त दस्तावेजों और आँकड़ों का विषयगत एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार अनुमानतः 239.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024 की तुलना में 12.1 प्रतिशत अधिक था। यह आर्थिक संबंधों के विस्तार को दर्शाता है, किंतु व्यापारिक वृद्धि अपने-आप नीतिगत मतभेदों की समाप्ति का प्रमाण नहीं है। अध्ययन संकेत करता है कि सेवा-वाणिज्य, निवेश, रक्षा-औद्योगिक सहयोग और उभरती प्रौद्योगिकियाँ संबंधों को व्यापक आधार प्रदान करती हैं। दूसरी ओर, बाजार पहुँच, नियामकीय असमानताएँ, संवेदनशील प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और रणनीतिक प्राथमिकताओं के अंतर सहयोग की सीमाएँ निर्धारित करते हैं। शोधपत्र का केंद्रीय निष्कर्ष है कि भारत–अमेरिका संबंधों की स्थिरता केवल सामरिक निकटता पर नहीं, बल्कि पारस्परिक आर्थिक लाभ, संस्थागत संवाद और विश्वसनीय क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत और अमेरिका के संबंधों को केवल व्यापारिक लेन-देन अथवा रक्षा खरीद तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता। वर्तमान द्विपक्षीय ढाँचे में व्यापार, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहयोग परस्पर जुड़े हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय इन संबंधों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है। इस साझेदारी की विशेषता विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत संपर्कों का विकास है, जिनमें सरकारी संवाद, उद्योगों की भागीदारी, विश्वविद्यालयों का सहयोग और लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। इसलिए इन संबंधों का अध्ययन आर्थिक और सामरिक आयामों को संयुक्त रूप से ध्यान में रखकर करना आवश्यक है ।

द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन को समझने के लिए इक्कीसवीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों का विशेष महत्त्व है। जनवरी 2004 में आरंभ हुई 'नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' पहल ने असैन्य परमाणु गतिविधियों, अंतरिक्ष और उच्च-प्रौद्योगिकी व्यापार में सहयोग की दिशा निर्धारित की। जुलाई 2005 की रणनीतिक पहल और इसके बाद परमाणु सहयोग संबंधी वार्ताओं ने संबंधों के विस्तार को गति दी। अतः 2004 की पहल को अंतिम असैन्य परमाणु समझौता मानना उचित नहीं है; वह आगे विकसित हुए सहयोग की प्रारंभिक संस्थागत अवस्था थी। इस अंतर को समझना ऐतिहासिक घटनाक्रम के सटीक विश्लेषण के लिए आवश्यक है।

आर्थिक संबंधों का विस्तार इस परिवर्तन का ठोस पक्ष है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय वस्तु-व्यापार लगभग 149.1 अरब डॉलर और सेवा-व्यापार लगभग 90.4 अरब डॉलर रहा। ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि सेवाएँ संबंधों का गौण नहीं, बल्कि प्रमुख घटक हैं। साथ ही, दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का असमान वितरण व्यापार-संतुलन और बाजार पहुँच से जुड़े प्रश्नों को महत्त्वपूर्ण बनाता है। इसलिए केवल कुल व्यापार की वृद्धि से संबंधों की गुणवत्ता का मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है; व्यापार की संरचना और उससे उत्पन्न लाभों का वितरण भी देखना आवश्यक है ।

सामरिक सहयोग भी आर्थिक साझेदारी से जुड़ रहा है। रक्षा-उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग का उद्देश्य व्यावसायिक लाभ के साथ तकनीकी क्षमता एवं आपूर्ति-श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाना है। फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में व्यापार, सैन्य सहयोग और प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाली COMPACT पहल इसी प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह दृष्टिकोण इस समझ पर आधारित है कि आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनेक क्षेत्र अब अलग-अलग नहीं रह गए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारत–अमेरिका संबंधों में व्यापार, निवेश, सेवा-क्षेत्र और रक्षा सहयोग की भूमिका का समेकित मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक संबंधों की प्रकृति, निवेश की पारस्परिकता, सेवा-वाणिज्य की उपयोगिता तथा रक्षा सहयोग के औद्योगिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। केंद्रीय शोध-प्रश्न यह है कि क्या बढ़ती आर्थिक सहभागिता और सामरिक सहयोग एक-दूसरे को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ा है कि सहयोग के विस्तार के बावजूद व्यापारिक विवाद और नीतिगत अंतर क्यों बने रहते हैं। अध्ययन में साझेदारी की मजबूती का अर्थ सभी मुद्दों पर समान नीति अपनाना नहीं, बल्कि मतभेदों के बीच सहयोग बनाए रखने की क्षमता माना गया है ।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का दस्तावेज-आधारित शोध है। इसमें द्वितीयक आँकड़ा-संग्रह पद्धति अपनाई गई है तथा प्राथमिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार अथवा क्षेत्रीय अवलोकन नहीं किए गए हैं। अध्ययन का आधार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़े और आधिकारिक दस्तावेज हैं। प्रमुख स्रोतों में भारतीय विदेश मंत्रालय का द्विपक्षीय संबंध विवरण, भारत–अमेरिका संयुक्त वक्तव्य, संसदीय प्रश्नों के आधिकारिक उत्तर और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के व्यापार-संबंधी विवरण शामिल हैं। ऐतिहासिक संदर्भ के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के अभिलेखीय विवरण का उपयोग किया गया है।

स्रोतों का चयन उनकी आधिकारिकता, विषय से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता, प्रकाशन-समय और आँकड़ों की स्पष्टता के आधार पर किया गया है। अध्ययन में सभी उपलब्ध दस्तावेजों की व्यवस्थित गणना प्रस्तुत नहीं की गई है; इसलिए इसे पूर्ण व्यवस्थित साहित्य-समीक्षा के बजाय चयनित आधिकारिक स्रोतों पर आधारित विश्लेषण समझना चाहिए। आर्थिक विश्लेषण में वर्ष 2025 के व्यापार आँकड़ों और वित्त वर्ष 2023–24 के निवेश आँकड़ों का उपयोग उनके संबंधित संदर्भों में किया गया है। अलग-अलग समयावधियों के आँकड़ों को एक ही वर्ष की स्थिति के रूप में प्रस्तुत करने से बचा गया है।

संकलित सामग्री को व्यापार, निवेश, सेवाएँ, रक्षा, प्रौद्योगिकी और नीतिगत चुनौतियों की विषयगत श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। संख्यात्मक जानकारी का प्रयोग संबंधों के आकार तथा दिशा को स्पष्ट करने के लिए किया गया है, जबकि संयुक्त वक्तव्यों और समझौतों का विश्लेषण संस्थागत प्राथमिकताओं की पहचान के लिए किया गया है। किसी पहल की घोषणा, समझौते पर हस्ताक्षर और वास्तविक क्रियान्वयन को अलग-अलग अवस्थाओं के रूप में देखा गया है। इस अंतर का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और प्राप्त परिणामों के बीच अनावश्यक समानता स्थापित करने से बचना है।

तुलना करते समय कैलेंडर वर्ष और भारतीय वित्त वर्ष के अंतर को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वार्षिक इक्विटी प्रवाह को संचयी निवेश अथवा घोषित परियोजना-मूल्य के समान नहीं माना गया है। उदाहरणतः वित्त वर्ष 2023–24 में अमेरिकी एफडीआई इक्विटी प्रवाह और फरवरी 2025 के वक्तव्य में उल्लिखित भारतीय कंपनियों की परियोजनाएँ अलग प्रकार के संकेतक हैं। इन्हें जोड़कर कुल द्विपक्षीय निवेश निकालना पद्धतिगत रूप से अनुचित होगा। अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। आधिकारिक दस्तावेज विश्वसनीय संस्थागत जानकारी देते हैं, लेकिन वे सरकारों की

प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को प्रमुखता दे सकते हैं। इस अध्ययन में उद्यमियों, कर्मचारियों अथवा उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष अनुभव सम्मिलित नहीं हैं। उपलब्ध सामग्री कारणात्मक प्रभाव का सांख्यिकीय परीक्षण भी संभव नहीं बनाती। इसलिए निष्कर्ष व्याख्यात्मक हैं; वे यह सिद्ध नहीं करते कि किसी विशेष समझौते से निश्चित मात्रा में व्यापार, रोजगार अथवा निवेश बढ़ा। इसी प्रकार किसी घोषणा को उसके बाद के सभी घटनाक्रमों की वर्तमान स्थिति का प्रमाण नहीं माना गया है।

चर्चा

भारत–अमेरिका व्यापार की संरचना में वस्तुओं और सेवाओं की संयुक्त भूमिका दिखाई देती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, 2025 में अमेरिका ने भारत को लगभग 45.4 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि भारत से उसका वस्तु-आयात लगभग 103.8 अरब डॉलर रहा। अमेरिकी वस्तु-व्यापार घाटा लगभग 58.4 अरब डॉलर था । ये आँकड़े भारत की अमेरिकी बाजार में मजबूत निर्यात-उपस्थिति और दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन को एक साथ दर्शाते हैं। व्यापार की बढ़ती मात्रा आर्थिक संपर्क की गहराई बताती है, लेकिन उसका असमान वितरण अलग-अलग घरेलू नीतिगत प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है।

इस असंतुलन का मूल्यांकन सावधानी से किया जाना चाहिए। व्यापार-घाटा अपने-आप अनुचित व्यापार का प्रमाण नहीं है; फिर भी वह घरेलू उद्योगों और रोजगार से संबंधित राजनीतिक बहसों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारतीय बाजार में शुल्क, तकनीकी मानकों, नियामकीय बाधाओं तथा कुछ क्षेत्रों में बाजार पहुँच संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया है। इस स्रोत को अमेरिकी पक्ष की आधिकारिक स्थिति के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि सभी विवादों का निष्पक्ष और अंतिम निर्णय मानना चाहिए। अध्ययन की दृष्टि में व्यापारिक असहमति का विश्लेषण दोनों देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं और घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में 'मिशन 500' के अंतर्गत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । उसी वक्तव्य में बहुक्षेत्रीय व्यापार समझौते के प्रथम चरण पर बातचीत की योजना भी प्रस्तुत की गई थी। यह महत्त्वाकांक्षा बाजार पहुँच और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण की राजनीतिक प्राथमिकता दर्शाती है। हालाँकि लक्ष्य को वास्तविक उपलब्धि तथा वार्ता की घोषणा को अंतिम समझौता नहीं माना जा सकता। इस प्रकार की पहलों का मूल्यांकन वास्तविक व्यापार-विस्तार, गैर-शुल्क बाधाओं में कमी और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की सरलता के आधार पर होना चाहिए। निवेश आर्थिक संबंधों को व्यापार से अधिक दीर्घकालिक आधार प्रदान कर सकता है, क्योंकि इससे उत्पादन-सुविधाएँ, प्रबंधन-संबंध और स्थानीय रोजगार जुड़े होते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। इस अवधि में अमेरिकी प्रवाह लगभग 4.99 अरब डॉलर रहा, जो कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग नौ प्रतिशत था। यह अमेरिकी पूँजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है, यद्यपि इसे भारत के समस्त विदेशी निवेश का अनुपात नहीं समझना चाहिए। निवेश-संबंध केवल अमेरिका से भारत की ओर प्रवाहित नहीं होते। फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में नोवेलिस, जेएसडब्ल्यू, एप्सिलॉन एडवांस्ड मैटेरियल्स और जुबिलेंट फार्मा जैसी भारतीय कंपनियों के अमेरिका में लगभग 7.35 अरब डॉलर के जारी निवेशों का उल्लेख किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय उद्यम अमेरिकी विनिर्माण और आपूर्ति-व्यवस्था में भी भागीदार बन रहे हैं। हालाँकि यह राशि चयनित परियोजनाओं की है, न कि अमेरिका में समस्त भारतीय निवेश की। इस द्विदिशात्मक प्रवाह से संबंधों की पारस्परिक आर्थिक उपयोगिता सामने आती है।

इस आधार पर अध्ययन का तर्क है कि निवेश की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल राशि से नहीं होना चाहिए। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी, कौशल-विकास, अनुसंधान-सहयोग और तकनीकी क्षमता का विस्तार अधिक उपयोगी संकेतक हैं । दोनों देशों के लिए ऐसी परियोजनाएँ अधिक लाभकारी होंगी जो अल्पकालिक प्रोत्साहनों से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धी उत्पादन और टिकाऊ व्यावसायिक संबंध स्थापित करें। निवेश-नीति का लक्ष्य केवल नई परियोजनाओं को आकर्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था से प्रभावी रूप से जोड़ना भी होना चाहिए।

सेवा-वाणिज्य भारत–अमेरिका आर्थिक संबंधों की विशेष पहचान है। वर्ष 2025 में अमेरिका का भारत को सेवा-निर्यात लगभग 42.9 अरब डॉलर और भारत से सेवा-आयात लगभग 47.6 अरब डॉलर था। वस्तु-व्यापार की तुलना में सेवा-वाणिज्य अधिक संतुलित दिखाई देता है। यह तथ्य इस धारणा को सीमित करता है कि दोनों देशों का आर्थिक संबंध केवल भारत के निर्यात अथवा अमेरिकी बाजार की एकतरफा उपलब्धता पर आधारित है। सेवा-क्षेत्र दोनों देशों के उद्यमों और पेशेवर समुदायों को जोड़ने वाला महत्त्वपूर्ण माध्यम है। डिजिटल और पेशेवर सेवाओं का विस्तार नियामकीय समन्वय से जुड़ा है। जनवरी 2024 के व्यापार नीति मंच के संयुक्त वक्तव्य में डिजिटल व्यापार, सेवाओं और पेशेवर योग्यताओं तथा अनुभव की मान्यता को महत्त्व दिया गया। इससे संकेत मिलता है कि सेवाओं के विस्तार में केवल माँग पर्याप्त नहीं है; प्रमाणन, पेशेवर मान्यता और कार्य-संबंधी प्रक्रियाएँ भी निर्णायक हैं। अध्ययन के अनुसार, इन क्षेत्रों में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता बढ़ने से उद्यमों की अनुपालन लागत कम करने और दीर्घकालिक व्यावसायिक निर्णयों को अधिक विश्वसनीय बनाने में सहायता मिल सकती है।

शिक्षा और अनुसंधान भी इस ज्ञान-आधारित संबंध का हिस्सा हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में लगभग 3,31,600 भारतीय विद्यार्थी अमेरिकी संस्थानों में अध्ययनरत थे। फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य ने विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की आवाजाही को पारस्परिक लाभ का स्रोत माना। इसलिए सेवा-क्षेत्र को केवल व्यावसायिक आउटसोर्सिंग तक सीमित करना उचित नहीं है। उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक नेटवर्क और अनुसंधान-संपर्क ज्ञान-आधारित आर्थिक सहभागिता का व्यापक सामाजिक आधार तैयार करते हैं।

रक्षा सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को नियमित संस्थागत आधार दिया है। जनवरी 2025 के भारतीय विदेश मंत्रालय के विवरण के अनुसार, अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद 20 अरब डॉलर से अधिक थी। इसमें परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और समुद्री निगरानी संबंधी प्लेटफॉर्म शामिल थे। यह संचयी खरीद-संबंधी विवरण है, किसी एक वर्ष का रक्षा-आयात नहीं। साथ ही, 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक विषयों पर समन्वय का प्रमुख मंच है। इस प्रकार रक्षा संबंध केवल उपकरणों की खरीद तक सीमित न रहकर नियमित नीतिगत विमर्श में भी परिवर्तित हुए हैं।

रक्षा संबंधों में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अर्थात् LEMOA, 2016; कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट अर्थात् COMCASA, 2018; और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट अर्थात् BECA, 2020 जैसे समझौते महत्त्वपूर्ण संस्थागत पड़ाव हैं। औद्योगिक सुरक्षा समझौता तथा आपूर्ति-सुरक्षा व्यवस्था भी सहयोग के ढाँचे में सम्मिलित हैं। इनका महत्त्व सहयोग के लिए प्रक्रियागत आधार तैयार करने में है। इनके अस्तित्व मात्र से प्रत्येक सैन्य अथवा राजनीतिक परिस्थिति में समान निर्णय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सैन्य अभ्यास परिचालन संपर्क बढ़ाने का अतिरिक्त माध्यम हैं। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रायम्फ जैसे अभ्यासों के अतिरिक्त दोनों देश बहुपक्षीय अभ्यासों में भी भाग लेते हैं। अध्ययन की दृष्टि में इन गतिविधियों का उपयोग केवल सैन्य क्षमता के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं की समझ और संस्थागत संवाद के विकास में भी है। फिर भी अभ्यासों की संख्या को साझेदारी की संपूर्ण गुणवत्ता का पर्याप्त मापदंड नहीं माना जाना चाहिए; उनके परिणाम और सहयोग की निरंतरता भी महत्त्वपूर्ण हैं।

रक्षा खरीद से आगे बढ़कर सह-विकास और सह-उत्पादन संबंधों का महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। मई 2023 का रक्षा-औद्योगिक सहयोग रोडमैप और जून 2023 में आरंभ INDUS-X पहल उद्योगों, विश्वविद्यालयों, निवेशकों तथा नवाचार संस्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित किए गए। मार्च 2025 के संसदीय उत्तर में जेट इंजन, गोला-बारूद और जमीनी गतिशीलता प्रणालियों से संबंधित प्राथमिक सह-उत्पादन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का उल्लेख है। ये प्रयास रक्षा सहयोग को औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी से जोड़ते हैं।

हालाँकि सह-उत्पादन और पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अलग अवस्थाएँ हैं। स्थानीय संयोजन से उत्पादन-अनुभव मिल सकता है, लेकिन डिजाइन, बौद्धिक संपदा और स्वतंत्र संशोधन की क्षमता स्वतः प्राप्त नहीं होती। फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में हथियार-हस्तांतरण नियमों तथा प्रौद्योगिकी-विनिमय की

बाधाओं की समीक्षा पर बल दिया गया। इससे अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि सहयोग की वास्तविक गहराई का मूल्यांकन तकनीकी पहुँच, स्थानीय मूल्य-वर्धन और दीर्घकालिक रखरखाव क्षमता के आधार पर होना चाहिए।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ आर्थिक और सामरिक सहयोग को जोड़ती हैं। जनवरी 2023 में आरंभ iCET का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग और नवाचार-तंत्रों के संपर्क को बढ़ाना था। फरवरी 2025 की TRUST पहल में रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, जैवप्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष को प्रमुख क्षेत्र बनाया गया। इन पहलों का विश्लेषण बताता है कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा केवल व्यावसायिक उत्पादकता नहीं, बल्कि आपूर्ति की विश्वसनीयता और संवेदनशील ज्ञान की सुरक्षा से भी जुड़ी है। परिणामस्वरूप आर्थिक अवसरों और सुरक्षा प्रतिबंधों के बीच संतुलन सहयोग की केंद्रीय आवश्यकता बन जाता है। ऊर्जा सहयोग में भी यही द्वैत दिखाई देता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में अमेरिका के साथ भारत का हाइड्रोकार्बन व्यापार लगभग 13.6 अरब डॉलर था। दूसरी ओर, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा-दक्षता, भंडारण और उभरते ईंधनों को स्थान दिया गया है। अध्ययन के अनुसार, ऊर्जा सहयोग की सफलता के लिए आपूर्ति-विविधीकरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को संतुलित करना आवश्यक होगा। इससे ऊर्जा संबंधों का मूल्यांकन केवल आयात-मात्रा के बजाय ऊर्जा संक्रमण में उनके योगदान के आधार पर भी किया जा सकेगा। असैन्य परमाणु सहयोग उपलब्ध अवसर और क्रियान्वयन-संबंधी कठिनाइयों का संयुक्त उदाहरण है। फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में अमेरिकी डिजाइन वाले रिएक्टरों, स्थानीयकरण, संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नागरिक परमाणु दायित्व से जुड़े विषयों पर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। यह बताता है कि राजनीतिक सहमति के बाद भी कानूनी, वित्तीय और औद्योगिक व्यवस्थाओं पर कार्य आवश्यक रहता है। इसलिए परमाणु सहयोग के संभावित लाभों और वास्तविक परियोजना-परिणामों को अलग रखना चाहिए।

बाह्य कारक संबंधों के अवसरों तथा सीमाओं को प्रभावित करते हैं। फरवरी 2025 के संयुक्त वक्तव्य में स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत, समुद्री सुरक्षा तथा निर्बाध वैध व्यापार पर बल दिया गया। उसी दस्तावेज में पाकिस्तान से संबंधित आतंकवाद और सीमा-पार हमलों की चिंताओं का उल्लेख किया गया। इससे आर्थिक संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा के बीच संबंध स्पष्ट होता है, क्योंकि सुरक्षित समुद्री मार्ग और स्थिर क्षेत्रीय वातावरण व्यापारिक विश्वास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

चीन तथा रूस से संबंधित प्रभावों का विश्लेषण अधिक व्यापक स्वतंत्र सामग्री की माँग करता है। प्रस्तुत अध्ययन के चयनित स्रोत इनके सभी पहलुओं का तुलनात्मक परीक्षण नहीं करते। इसलिए इनके प्रभाव का निश्चित परिमाण बताना उचित नहीं होगा। विश्लेषणात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि साझेदारी की स्थिरता का मूल्यांकन करते समय तीसरे देशों के प्रति पूर्ण नीतिगत समानता के बजाय असहमति सँभालने की क्षमता देखनी चाहिए। भारत के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग का विस्तार स्वतंत्र निर्णय-क्षमता के साथ संतुलित रहना इस अध्ययन का महत्त्वपूर्ण नीतिगत विचार है।

सहयोग के प्रमुख अवसर उच्च-मूल्य विनिर्माण, डिजिटल सेवाओं, रक्षा नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति-श्रृंखलाओं में दिखाई देते हैं। फरवरी 2025 का संयुक्त वक्तव्य इन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश, अनुसंधान तथा औद्योगिक सहभागिता को बढ़ाने पर बल देता है। किंतु अवसरों को परिणाम में बदलने के लिए परियोजना-स्तरीय वित्त, कौशल, मानकों और नियामकीय प्रक्रियाओं का समन्वय आवश्यक होगा। इसके अभाव में राजनीतिक घोषणाएँ वास्तविक आर्थिक उपलब्धियों में परिवर्तित नहीं हो सकेंगी।

व्यापार नीति मंच मतभेदों के प्रबंधन का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। मार्च 2025 के आधिकारिक संसदीय उत्तर के अनुसार, 2023 में दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन में अपने सात लंबित व्यापार विवादों का समाधान किया। यह उदाहरण बताता है कि विवादों का अस्तित्व साझेदारी की विफलता नहीं है; अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्हें हल करने के लिए प्रभावी संस्थाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। नियमित संवाद आर्थिक असहमति को व्यापक रणनीतिक सहयोग पर हावी होने से रोकने में उपयोगी हो सकता है। अध्ययन के आधार पर नीति की प्राथमिकता पूर्वानुमेय नियम, पारदर्शी तकनीकी शर्तें और नियमित प्रगति-मूल्यांकन होना चाहिए। निवेश को स्थानीय कौशल तथा आपूर्तिकर्ता-विकास से, सेवा-सहयोग को पेशेवर मान्यता से और रक्षा-सहयोग को

रखरखाव तथा तकनीकी क्षमता से जोड़ना उपयोगी होगा। साथ ही, प्रगति का आकलन घोषणाओं की संख्या के बजाय पूर्ण परियोजनाओं, परिचालित उत्पादन-क्षमताओं और वास्तविक बाजार पहुँच से किया जाना चाहिए। इससे साझेदारी के लाभों का अधिक स्पष्ट और उत्तरदायी मूल्यांकन संभव होगा।

प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन का पहला निष्कर्ष यह है कि भारत–अमेरिका आर्थिक संबंध वस्तु-व्यापार से कहीं व्यापक हैं। वर्ष 2025 में 239.6 अरब डॉलर के कुल व्यापार में 90.4 अरब डॉलर का सेवा-वाणिज्य इस व्यापकता को स्पष्ट करता है। सेवाओं का अपेक्षाकृत संतुलित प्रवाह संबंधों की पारस्परिक उपयोगिता को भी रेखांकित करता है। इसलिए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का विश्लेषण केवल वस्तु-व्यापार घाटे के आधार पर करना अधूरा होगा।

दूसरा निष्कर्ष निवेश की द्विदिशात्मक प्रकृति से संबंधित है। भारत में अमेरिकी एफडीआई और अमेरिका में भारतीय कंपनियों की परियोजनाएँ दर्शाती हैं कि संबंध केवल एक देश द्वारा दूसरे को पूँजी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं। हालाँकि विभिन्न निवेश संकेतकों की प्रकृति अलग होने के कारण उनकी सीधी तुलना सीमित है। निवेश की गुणवत्ता समझने के लिए स्थानीय उत्पादन, कौशल और तकनीकी क्षमता से जुड़े परिणामों का अलग मूल्यांकन आवश्यक है।

तीसरा निष्कर्ष रक्षा सहयोग के संस्थानीकरण का है। नियमित संवाद, आधारभूत समझौते और नवाचार मंच संबंधों को निरंतरता प्रदान करते हैं। फिर भी तकनीकी हस्तांतरण, स्वदेशी क्षमता और आपूर्ति-विश्वसनीयता का मूल्यांकन रक्षा खरीद के आकार से अलग करना आवश्यक है। खरीद-संबंधों का विस्तार महत्त्वपूर्ण है, लेकिन औद्योगिक आत्मनिर्भरता में वास्तविक योगदान अधिक गहन परीक्षण की माँग करता है।

चौथा निष्कर्ष आर्थिक सुरक्षा की बढ़ती केंद्रीयता है। सेमीकंडक्टर, खनिज, ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रस्तावित सहयोग दर्शाता है कि आर्थिक निर्णय और सुरक्षा प्राथमिकताएँ अधिक निकट आ रही हैं। यह निकटता अवसर पैदा करती है, किंतु संवेदनशील प्रौद्योगिकी की सुरक्षा तथा बाजार-खुलेपन के बीच संतुलन भी माँगती है। तकनीकी सहयोग की प्रगति इस संतुलन के प्रबंधन पर निर्भर करेगी।

अंततः, अध्ययन का व्याख्यात्मक निष्कर्ष है कि साझेदारी का स्थायित्व स्वतः सुनिश्चित नहीं है। उपलब्ध साक्ष्य सहयोग के व्यापक संस्थागत आधार का समर्थन करते हैं, लेकिन व्यापारिक वृद्धि अथवा राजनीतिक घोषणाएँ अकेले दीर्घकालिक परिणाम सिद्ध नहीं करतीं। विश्वसनीय क्रियान्वयन, लाभों की पारस्परिकता और मतभेद-प्रबंधन निर्णायक रहेंगे। इन निष्कर्षों को दस्तावेज-आधारित विश्लेषण के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि कारणात्मक सांख्यिकीय परीक्षण के परिणाम के रूप में।

निष्कर्ष

भारत–अमेरिका संबंधों के आर्थिक और सामरिक आयाम एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। व्यापार और सेवाएँ आर्थिक हितों का विस्तार करते हैं, निवेश उत्पादन-संबंधों को मजबूत करता है और रक्षा तथा तकनीकी सहयोग संस्थागत संपर्क बढ़ाते हैं। उपलब्ध आधिकारिक सामग्री एक बहुक्षेत्रीय साझेदारी की दिशा स्पष्ट करती है, जिसमें बाजार, ज्ञान, औद्योगिक क्षमता और सुरक्षा की आवश्यकताएँ संयुक्त भूमिका निभाती हैं। इस व्यापकता के कारण संबंधों का मूल्यांकन किसी एक विवाद, समझौते अथवा व्यापारिक आँकड़े के आधार पर नहीं किया जा सकता।

इस शोधपत्र का केंद्रीय तर्क है कि संबंधों का भविष्य केवल बढ़ते व्यापार अथवा रक्षा सौदों पर निर्भर नहीं करेगा। निर्णायक प्रश्न यह होगा कि क्या दोनों देश सहयोग से मिलने वाले लाभों को व्यापक, संतुलित और विश्वसनीय बना पाते हैं। इसके लिए भारत को तकनीकी सीख, कौशल और घरेलू उत्पादन-क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, जबकि द्विपक्षीय स्तर पर पारदर्शी नियम, नियमित संवाद और पारस्परिक प्राथमिकताओं के प्रति सम्मान आवश्यक होंगे। आर्थिक सहयोग को सामाजिक तथा औद्योगिक क्षमता-विकास से जोड़ना साझेदारी को अधिक टिकाऊ बना सकता है।

अतः इन संबंधों को सशर्त रूप से स्थायी रणनीतिक साझेदारी की दिशा में विकसित होता हुआ समझा जा सकता है। यह निष्कर्ष न तो सभी मतभेदों की समाप्ति का दावा करता है और न भविष्य की अनिवार्य सफलता का। इसका आधार यह है कि आर्थिक, तकनीकी और रक्षा संस्थाएँ सहयोग के लिए

मजबूत संरचना प्रदान करती हैं। उस संरचना को दीर्घकालिक परिणामों में बदलना निरंतर नीतिगत प्रयास, स्वतंत्र निर्णय-क्षमता के सम्मान और वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. Ministry of External Affairs, Government of India. (2005, July 18). Joint statement, India–
2. Office of the United States Trade Representative. (2024, January 5). Ambassador Katherine Tai to travel to India.
3. Ministry of External Affairs, Government of India. (2006, March 7). Implementation of the India–United States joint statement of July 18, 2005: India's separation plan.
4. Office of the United States Trade Representative. (2025.). India. पृष्ठ संख्या: उपलब्ध नहीं; संबंधित अनुभाग: "India Trade Summary."
5. Ministry of External Affairs, Government of India. (2025, February 13). India–U.S. joint statement.
6. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. (2024). Focus year: 2023–24.
7. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. (2024). *Focus year: 2023–24.*
8. Institute of International Education. (2024, November 18). United States hosts more than 1.1 million international students at higher education institutions, reaching all-time high.
9. U.S. Department of Defense. (2023, June 5). Roadmap for U.S.–India defense industrial cooperation.
10. Ministry of Defence, Government of India. (2023, June 22). India–United States Defence Acceleration Ecosystem (INDUS X) launched in Washington DC, U.S. Press Information Bureau.
11. Mishra, V. (2023, February 9). iCET: Upscaling India–US partnership for a tech-centric future. Observer Research Foundation.
12. Ray, T. (2024, October 11). India–U.S. technology ties: Charting an ambitious course for the future (ORF Issue Brief No. 739). Observer Research Foundation.
13. Parpiani, K. (2024, August 29). Biden, Trump, and India–US technology partnership (ORF Occasional Paper No. 447). Observer Research Foundation.
14. Tellis, A. J. (2023, November 27). Completing the U.S.–India civil nuclear agreement: Fulfilling the promises of a summer long past. Carnegie Endowment for International Peace.

Cite the Article:

कुमार, अरुण, सुमन, डॉ. (2026). भारत–अमेरिका संबंधों के आर्थिक और सामरिक आयाम: व्यापार, निवेश, सेवा-क्षेत्र तथा रक्षा सहयोग में अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन. The Research Dialogue, 5(3), 239–245. DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i3.27

Disclaimer: The views, opinions, interpretations, analyses, conclusions, recommendations, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) bear full responsibility for the originality, accuracy, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring compliance with applicable academic and ethical standards, including those relating to plagiarism, AI-generated or AI-assisted content, copyright infringement, data fabrication or falsification, and other forms of research or academic misconduct.